

Use more MPLADS funds for irrigation: Pawar to MPs

RAVISH TIWARI

NEW DELHI, AUGUST 25

GOING a step ahead of Congress president Sonia Gandhi, NCP leader and Agriculture Minister Sharad Pawar has urged all MPs to devote a higher share of their MP Local Area De-

With scant rainfall, farmers use pots to water land in Sangli, Maharashtra, on Tuesday. PTI

velopment Scheme (MPLADS) funds for irrigation and drought-proofing works in their respective constituencies.

Pawar has sent a letter to all MPs requesting them to recommend projects such as construction of tube wells, farm forestry, desilting of ponds, irrigation works, strengthening irrigation embankments and drinking water projects under the MPLADS funds with them to tackle drought and meet the irrigation re-

quirements of the next rabi crop.

The NCP leader's suggestion comes soon after Congress president Sonia Gandhi asked party legislators to contribute 20 per cent of their basic salary — for one year — to meet the challenges of the drought-like situation in large parts of the country.

If Pawar's appeal has the intended effect, each MP can recommend works up to Rs 2 crore every year in their respective constituencies. The records available with the govern-

ment indicate that irrigation is a much-neglected area.

According to the latest annual report (2007-08) of the MPLAD Scheme, irrigation comprised less than 2 per cent of projects, which adds up to less than 3 per cent in monetary terms of total works recommended by the MPs in their constituencies.

Most MPs have focused more on recommending works pertaining to roads and bridges (29.44 per cent of works), other public facilities (27.98

per cent), and education (17.38 per cent). Drinking water projects, primarily hand pumps, comprise about 11 per cent of MPs' works in this category.

Only last week Pawar had asked the state agriculture ministers to use the funds under the Rural Infrastructure Development Fund (RIDF) with NABARD to undertake rapid construction of shallow tubewells to meet the irrigation requirements of the next Rabi crop.

होमा फार्मिंग से उगाएं फसल

रोशन/एसएनबी

नई दिल्ली। आप यकीन करेंगे, कृषि विश्वविद्यालय वैज्ञानिक आधार पर खेती करने और फसलों की बीमारियों को दूर करने के बजाए मंत्रोच्चारण और यज्ञ कराकर फसलों की बीमारी दूर रहा है। इस पर यकीन करना मुश्किल है, पर यह सच है। पालमपुर स्थिति कृषि विश्वविद्यालय में वैज्ञानिकों की 20 टीमों होमा फार्मिंग कर रही हैं। स्थानीय किसानों से भी करा रही है। ब्राजील ने भारत की इस वैदिक पद्धति का अनुसरण किया है।

इस हकीकत का पता लगाने के लिए हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय के उप कुलपति डा. तेजपाल से संपर्क किया गया तो उन्होंने उत्साहित होकर इस वैदिक प्रयोग की बात स्वीकारी और कहा कि उनका यह प्रयोग बेहद सफल है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद भी इस तरह की खेती को बढ़ावा देने के लिए मदद कर रहा है।

विश्वविद्यालय के आर्गेनिक फार्मिंग के विभागाध्यक्ष डा. वाईएस पॉल ने 'राष्ट्रीय सहारा' को होमा फार्मिंग के बारे में विस्तार से बताया। उन्होंने कहा कि हमने वर्ष 2006 में होमा फार्मिंग की शुरुआत की। होमा फार्मिंग के अलावा पांच तरह

किस्म की फार्मिंग होती है जिसमें वैदिक व आध्यात्मिक पद्धति अपनाई जाती है। इस प्रक्रिया में मंत्रोच्चारण और यज्ञ दो तरीके से होता है। एक सूर्योदय के समय और दूसरा सूर्यास्त के समय। पहला यज्ञ अग्निहोत्र और दूसरा त्रयम्बक। अग्निहोत्र में चावल को देसी घी में मिलाकर उपले के पिरामिड में आहुति देते हैं। आहुति देते

**हिमाचल प्रदेश कृषि विवि ने
शुरू की खेती की नई पद्धति**

**भारत की इस पद्धति का
ब्राजील ने किया अनुसरण**

वक्त सूर्याहा स्वाहः और सूर्यये इदमम् प्रजापतिये स्वाहा और प्रजापतिये इदमम् नमः, सूर्यास्त के समय अग्नियेय स्वाहः, अग्नियेय इदम नमः, प्रजापतिये स्वाहः प्रजापतिये इदम नमः मंत्र बोला जाता है। दूसरा यज्ञ त्रयम्बक है जो दो घंटे सुबह और दो घंटे सायं को चलता है। इसमें महामृत्युंजय मंत्र बोला जाता है।

यज्ञ से निकली भस्म को या तो सीधे खेतों में डाल देते हैं या गोबर और दूसरे मिश्रण के साथ डालते हैं। एक बार के यज्ञ

से 48 हेक्टेयर भूमि का शुद्धिकरण और ऊर्जाकरण हो जाता है। डा. पॉल के अनुसार, हमने यज्ञ का वैज्ञानिक अनुसंधान और माइक्रोबायोलॉजी अध्ययन कराया। यज्ञ वाले क्षेत्र के सूक्ष्म विषाणु तक मर जाते हैं। इस यज्ञ और यज्ञ भस्म से ऐसी बीमारियां ठीक हुई हैं जो दवाइयों से ठीक नहीं होती। उन्होंने कहा कि वैज्ञानिकों की 20 टीमों बनाई गई हैं जो होमा फार्मिंग का बारीकी से अध्ययन कर रही है।

होमा फार्मिंग को मटर, मक्का व सोयाबीन पर अजमाया गया। उत्पादन में 10-15 प्रतिशत की वृद्धि हुई। होमा फार्मिंग की शुरुआत के समय विवि की खूब आलोचना हुई। हमने लोगों के सामने साक्ष्य पेश किए। फिर लोगों ने स्वीकारा। अब तो केंद्र सरकार की तरफ से भी इस होमा फार्मिंग को समर्थन मिल रहा है। आईसीएआर ने हमारे एक प्रोजेक्ट को स्वीकार कर लिया है। यह पद्धति ब्राजील में अपनाई गई है। इस पद्धति से उन्हें केले की बीमारी 'सिगाटोका' को रोकने में मदद मिली है। विश्वविद्यालय के उपकुलपति डा. तेजपाल कहते हैं कि आध्यात्मिक रास्ते पर चलने में दिक्कत तो होती है। वह कहते हैं कि वे इकोलॉजी यानि पारिस्थितिकी के विद्यार्थी हैं।

सिंचाई के कारबिल नहीं दर्जनों जोहड़

पश्चिमी दिल्ली, जागरण संवाददाता : दिल्ली देहात के किसानों की सुविधा के लिए यहां के गांवों में बाढ़ एवं सिंचाई विभाग द्वारा दर्जनों जोहड़ बनवाए गए हैं। लेकिन बेमन से बनाए गए इस जोहड़ में खेतों का एक बूंद पानी भी नहीं जाता है। ऐसे में ये जोहड़ सूख गए हैं।

खेती में पानी की किल्लत को देखते हुए बाढ़ एवं सिंचाई विभाग द्वारा हर गांव में दो से तीन जोहड़ बनाए गए थे। इनमें जरूरत से ज्यादा पानी को संचित कर दिया जाता है। इससे सिंचाई में पानी की किल्लत महसूस नहीं होती। लेकिन इसकी दीवार करीब चार फीट ऊंची होने से इसमें पानी इकट्ठा नहीं हो पाता है। कई जोहड़ ऐसे हैं जिसकी दीवार के निचले हिस्से में खेतों व नाले का पानी रुकने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। जाफरपुर निवासी सुरजभान यादव ने कहा इसे बनाने में भले ही विभाग ने लाखों रुपये खर्च किए हों। लेकिन सच्चाई यह है कि इसका उपयोग न के बराबर है। इसमें सिर्फ बरसात का पानी गिर सकता है। बाहर का पानी इसके अंदर आ ही नहीं सकता। ग्रामीण शिक्षा एवं साहित्य एसोसिएशन के अध्यक्ष सुरेंद्र सिंह गहलोत ने कहा कि हमें खुशी थी कि हमारी खेती पानी की किल्लत से मारी नहीं जाएगी, लेकिन बाढ़ में पता चल रहा है कि यह हमारे किसी काम की नहीं है।

Weak monsoon hits groundnut farming

By **S.P.S. Pannu**
in New Delhi

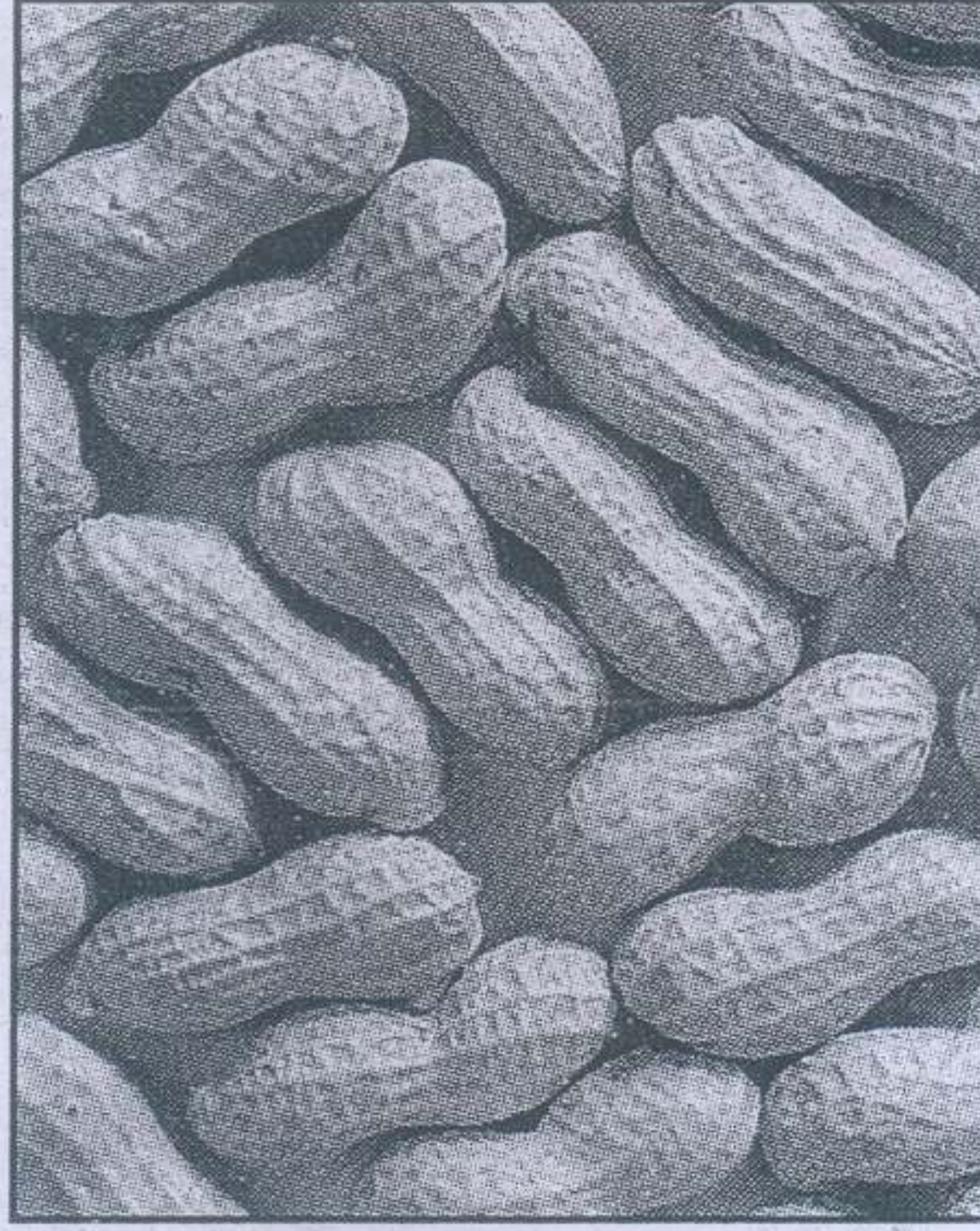
THERE has been a sharp decline in the acreage under groundnut cultivation due to the weak monsoon, which is bound to lead to an increase in edible oil prices and higher quantum of imports.

According to the latest figures compiled by the ministry of agriculture, the area under groundnut cultivation has come down by as much as 22 per cent to 35.7 lakh hectares in the current kharif season from 45.5 lakh hectares last year.

Over 40 per cent of the country's requirement of edible oils is met through imports and this proportion is expected to go up due to the reduction in the area under groundnut cultivation this year.

Edible oil imports had jumped by over 45 per cent to a whopping Rs 15,873.6 crore for the financial year ended March 31, 2009 from Rs 10,942.54 crore in 2007-08. This is expected to shoot up further during the current year.

Since India buys edible oils in large quantities, given the



The area under groundnut cultivation has come down by as much as 22%

size of its population, the prices in the international market shoot up each time the country decides to import. The fact that the rupee has depreciated further will only make these imports costlier and further accentuate inflationary pressures.

China and India are the largest producers of groundnut in the world and also the largest consumers.

According to commodity expert Mehul Agarwal, groundnut is also exported to Europe and America but has recently lost ground as the soyabean

lobby has been highlighting the fact that it contains toxic elements harmful to humans.

He is of the view that this could also be one of the reasons for the reduced area under the crop and

Imports meet over 40% of India's edible oil need

an increase in the area under soyabean.

However, the acreage under soyabean, which also requires less water than groundnut, has gone up by around two lakh

tonnes and cannot compensate for the loss in acreage under groundnut.

There has been some increase in the area under cultivation of pulses as prices are ruling high and they also require less water to grow.

Oilseeds are a weak link in Indian agriculture and have forced the country to go in for heavy imports of edible oils, which the country can ill-afford at a time when exports have slowed down and the trade deficit has widened.

sps.pannu
@mailtoday.in